गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 278
दि. 09.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

जापान की पीएम सनाए ताकाइची की संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत, पीएम मोदी ने बधाई दे कही ये बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को प्रतिनिधि सभा के चुनाव में उनकी 'ऐतिहासिक जीत' पर बधाई दी। ताकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनाव में बहुमत मिला है।

नई दिल्ली (जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। चुनाव नतीजों पर उन्हें बधाई देते हुए पीएम मोदी ने भारत-जापान संबंधों के महत्व पर जोर दिया। दोनों देशों के संबंध एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर आधारित हैं। साथ ही, यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में अहम भूमिका निभाते हैं।

पीएम मोदी ने ट्वीट में क्या लिखा?

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में आपकी शानदार जीत पर सनाए ताकाइची को बधाई। हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप दुनिया में शांति, स्थिरता और खुशहाली बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। मुझे भरोसा है कि आपके काबिल नेतृत्व में हम भारत-जापान दोस्ती को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

ताकाइची ने अचानक हुए निचले सदन के चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीनों

बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उनकी रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP), गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर, दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की उम्मीद है। इससे उनकी सरकार को अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में निर्णायक बढ़त मिलेगी।

जापान की पहली महिला पीएम

64 साल की ताकाइची अक्टूबर में छठ्ठ की लीडरशिप जीतने के बाद जापान की प्रधानमंत्री बनीं। इसके साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनीं। ताकाइची रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और चीन पर अपने कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने खुद को अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समान सोच वाले पार्टनर्स के साथ करीबी सहयोग की एक मजबूत समर्थक के तौर पर पेश किया है। उनकी जीत महंगाई, फंडिंग घोटालों और वोटरों की नाराजगी जैसी राजनीतिक उथल-पुथल के सालों बाद LDP के लिए एक बड़ा बदलाव है।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, सीतापुर दो दिन के लिए 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित

(जीएनएस)।

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 9 फरवरी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जिले को दो दिनों के लिए नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश रविवार से प्रभावी होकर सोमवार शाम कार्यक्रम के समापन तक लागू रहेगा।

नो-फ्लाइंग जोन के तहत जिले की सीमा में ड्रोन उड़ाने, गुब्बारे छोड़ने और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ शहर के लोनियनपुरवा अंतर्गत शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित तपोधाम आश्रम में आयोजित गोरखनाथ प्रतिमा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने 9 फरवरी को आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

शनिवार देर शाम आईजी जोन लखनऊ किरण एस ने स्वयं कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए।

हरिहरा गांव में तस्करी के लिए गौवंश ले जा रही बोलेरो हादसे का शिकार ये खबर भी पढ़े : हरिहरा गांव में तस्करी के लिए गौवंश ले जा रही बोलेरो हादसे का शिकार

मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जीआईसी मैदान में हेलीपैड तैयार कराया गया है। यहां से कार्यक्रम स्थल तक करीब दो किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके।

सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए कार्यक्रम स्थल व अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। इसके साथ ही पुलिस ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है और तैयारी भी पूरी कर ली गई हैं।

प्रधानमंत्री की मलेशिया में व्यापार प्रमुखों के साथ बैठक

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मलेशिया के चार प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। उन्होंने पेट्रोनास के अध्यक्ष और समूह सीईओ तन श्री तेंगकू मुहम्मद तौफिक; बरजाया कॉर्पोरेशन बरहाद के संस्थापक तन श्री दातो सेरी विंसेंट तन ची यिउन; खजानाह नेशनल बरहाद के प्रबंध निदेशक दातो अमीरुल फैसल वान जाहिर; और फि सन इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक दातो पुआ खेन सेंग से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते व्यापार-से-व्यापार संबंधों और भारतीय विकास गाथा में मलेशियाई कंपनियों की गहरी रुचि की सराहना की। उन्होंने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और एक स्थिर, कुशल और पूर्वानुमानित व्यापार एवं नीतिगत वातावरण बनाने के लिए हाल के वर्षों में भारत में की गई पहलों और सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने मलेशियाई व्यवसायों को विशेष रूप से अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में भारत द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी 2026 को कुआला-लंपुर में आयोजित होने वाले 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इन चचाओं से भारत-मलेशिया व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

उद्योग जगत के प्रमुखों ने भारत सरकार द्वारा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में किए गए सुधारों की प्रशंसा की और भारत की विकास गाथा में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने अपने निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करके और भारतीय समकक्षों के साथ संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं को तलाशकर भारत में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई।

'मेरी हत्या कराना चाहते हैं मुकेश रौशन, पीएम से मिलूंगा', तेज प्रताप का सनसनीखेज आरोप, 5 जयचंदों का बताया नाम

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कई गंभीर

आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से निकालने और उनकी छवि को धूमिल करने में "जयचंदों" का हाथ है। यादव ने इस मामले में पूर्व विधायक मुकेश रौशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह और सुनील सिंह का नाम लिया है।

'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में साप्ताहिक पत्र 'ऑर्गेनाइजर' के 'भारत प्रकाशन' द्वारा प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि ऑर्गेनाइजर हमेशा से अंग्रेजी पत्रकारिता में मूल भारत का विचार रखता आया है, उस पर दृढ़ रहा है और उसके अनेक आयामों को भारतीय जनता के सामने रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज Chhattisgarh @ 25: Shifting the Lens का सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता शब्द किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसकी रचना आजादी के बाद हुई, उसके लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का प्रयोग सिर्फ प्रयोग मात्र नहीं है बल्कि वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के समय एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की रचना का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सफल होने से ही संपूर्ण विश्व स्थिर और समृद्ध होगा, यह आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल के दौरान बने नए राज्यों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन

केन्द्र में पिछली सरकार के दौरान बनने वाले एक नए राज्य तेलंगाना के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में बहुत अधिक कटुता हो गई जो एक दशक से भी अधिक समय तक चली। उन्होंने कहा कि आज भी दोनों राज्यों के बीच कई विवाद लंबित हैं। श्री शाह ने कहा कि उनकी पार्टी और इतने अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं तो इन राज्यों जैसी कटुता हो जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आइडियोलॉजी की बहुत भूमिका होती है और यही शासन को चलाती है। जिस राजनीतिक दल की विचारधारा ही न हो, वह राजनीतिक दल राज्य या देश का भला नहीं कर सकता।

श्री अमित शाह ने कहा कि पत्रकारिता जगत में ऑर्गेनाइजर ने देश के मुद्दों पर हमेशा आइडियोलॉजी के आधार पर उचित और उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का धर्म विचार को डरे बिना निर्भीक रूप से रखना है और ऑर्गेनाइजर ने निर्भीकता कभी नहीं छोड़ी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले ऑर्गेनाइजर का मजाक उड़ाया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था और उसका विरोध किया जाता था लेकिन इन तीनों कालखंड में भी ऑर्गेनाइजर दृढ़ता के साथ विचारधारा का दृष्टिकोण रखने से कभी नहीं डरा। श्री शाह ने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत की यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है जिसे कोई इतिहासकार नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि देश और समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संघ के स्वयंसेवकों का सबसे अधिक सकारात्मक योगदान न हो।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ 25 वर्ष का हो गया है और गत 25 वर्षों में राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इक्टअफ्च प्रदेश कहा जाता था। और विकसित राज्य बनने की कगार पर खड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि इसका बहुत बड़ा कारण यहां लंबे समय तक उनकी पार्टी की सरकार बनीं और विकास का दौर चला। श्री शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकारों ने सुशासन और शासन के अनेक प्रकार के मानांक गढ़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 25 साल पहले इक्टअफ्च और नक्सलवाद से ग्रस्त राज्य माना जाता था।

वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए उमड़ी भीड़, एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम, वीडियो जमकर हुआ वायरल

भारतीय क्रिकेट के भविष्य ने एक बार फिर दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है।

जिम्बाब्वे की धरती पर अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम आज जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, तो वहां का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था।

हाथों में तिरंगा, ढोल-नगाड़ों की थाप और 'वर्ल्ड चैंपियंस' के नारों के साथ फैंस ने अपने इन युवा सितारों का पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत किया। करीब एक महीने तक चले कड़े संघर्ष के बाद छठी बार 'विश्व विजेता' का टैग लेकर लौटे इन खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ देखी जा सकती थी।

नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, डोभाल और कनाडा एनएसए के बीच बनी सहमति, खालिस्तानी संगठनों की खैर नहीं

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की ओटावा यात्रा के दौरान, भारत और कनाडा सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की स्थापना पर सहमत हुए हैं।अजीत डोभाल ने अपनी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रौइन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता की है। इस बैठक से स्पष्ट संकेत मिला है कि हिंसक चरमपंथी समूहों को अब कनाडाई सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है ।

डोभाल कनाडा की दो दिवसीय यात्रा पर थे, जहाँ उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री की उप-क्लर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया सलाहकार नथाली ड्रौइन से मुलाकात की। यह बैठक भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य आपसी सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

विदेश मंत्रालय (MEA) की विज्ञप्ति अनुसार, ठरअ की दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने

कामकाजी संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए, जो द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा है।

भारत-कनाडा संबंधों में दिखा स्पष्ट "रीसेट"

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई भारत-कनाडा वाताओं से द्विपक्षीय संबंधों में एक स्पष्ट "रीसेट" देखने को मिला है। बातचीत के दौरान कनाडा की ओर से यह कड़ा संदेश दिया गया कि खालिस्तान-समर्थक नेटवर्क जैसे हिंसक चरमपंथी समूहों को अब कनाडाई सरकार का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। यह बदलाव भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कनाडा के राजनीतिक रुख से कानून-प्रवर्तन आधारित कार्रवाई की ओर संकेत करता है।

खुफिया जानकारी साझा करना रहा मुख्य फोकस

सूत्रों ने बताया कि इन वाताओं का मुख्य केंद्र नशीले पदार्थों, साइबर खतरों और चरमपंथ से जुड़ी वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करना था।

ग्राम रायपुर में हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन के आरोप में विवाद, तीन लोगों पर केस दर्ज–लालच देने का आरोप

(जीएनएस)।

खंडवा जिले के थाना पिपलोद क्षेत्र के ग्राम रायपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामवासी विजय कुमार राठौर (32) ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि गांव के तीन लोग- नवलसिंह बारेला, दशरथ विश्वकर्मा और रमेश बारेला-पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन का प्रचार-प्रसार कर रहे थे।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता विजय कुमार राठौर ने थाना पिपलोद में दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उन्हें और अन्य ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिया। आरोप है कि उन्होंने कहा-"ईसाई धर्म अपनाओगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, घर में सुख-शांति रहेगी और बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 से 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।" शिकायत में यह भी कहा गया कि शनिवार को आरोपियों द्वारा प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थीं, जिसमें बीमार लोगों को ठीक करने की प्रार्थना की जाती थी।

विरोध करने पर मारपीट और धमकीं

शनिवार रात जब विजय कुमार

गांव के सरपंच पति, उपसरपंच पति और अन्य ग्रामीणों के साथ आरोपियों के घर पहुंचे और धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई और मारपीट की। विजय कुमार को पीठ पर अंदरूनी चोटें आईं। घटना के दौरान गांव के कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए और बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने धमकी भी दी कि "धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो जान से खत्म कर देंगे।"

शिकायत के आधार पर थाना पिपलोद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धारा 299 (धर्म परिवर्तन के लिए लालच), 351(2) (मारपीट), 351(3) (गंभीर चोट), 351(4) (धमकी) और अन्य संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस जांच और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

पुलिस अधीक्षक खंडवा ने बताया कि शिकायत मिलते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रार्थना सभाओं और लालच देने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध हुए तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश है। कई लोग कह रहे हैं कि गांव में पिछले कुछ समय से ईसाई प्रचार बढ़ा है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हमारे गांव में सदियों से हिंदू परंपराएं चली आ रही हैं। कुछ लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यह गलत है।"

धर्म परिवर्तन कानून का संदर्भ

मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें जबरन, लालच या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है। यदि लालच या धमकी के सबूत मिलते हैं, तो आरोपियों के खिलाफ 5 साल तक की सजा और जुमार्ना हो सकता है। यदि नाबालिग या महिला शामिल है तो सजा 10 साल तक हो सकती है।

यह मामला अब जिले में गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की है और जांच तेज कर दी है। यदि आरोप सिद्ध हुए तो यह धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ा केस बन सकता है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

सोशल मीडिया और कूटनीतिक क्षेत्र में मानचित्र की वजह से हलचल

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप प्राशासन के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रातिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा जारी किया गया भारत का मानचित्र पाक अधिवृत कश्मीर (पीओके) और अक्साईं चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। भले ही यह मानचित्र चुपचाप जारी किया गया हो किन्तु सोशल मीडिया और वूटनीतिक क्षेत्र में इस मानचित्र की वजह से अत्याधिक हलचल मची हुईं है।

इससे एक बात तो साफ हो गईं है कि अमेरिका अब महसूस करने लगा है कि यदि वह भारत के साथ संबंध अच्छे कर ले जाए तो निति रूप से एशिया में वह बुलंदियों को छू सकता है। इसलिए इस मानचित्र के जारी होने को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को तो वह आईएमएफ, विश्व बैंक और खाड़ी के देशों से उधार दिलवाकर अपने वश में रख सकता है किन्तु भारत को अपने साथ खड़ा रखने के लिए उसके साथ ठोस रणनीतिक संबंध बनाना जरूरी है। भारत कोईं जवाब दे या न दे, अमेरिका ने भारत को स्पष्ट एवं दो टूक जवाब दे दिया है कि नईं दिल्ली के दोनों पड़ोसियों द्वारा थोपी गईं रणनीतिक समस्याओं को लेकर अमेरिका भारत के साथ ही रहेगा। पूर्व में पीओके के मामले में अमेरिका ने पहले तो अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने 1971 के बाद स्पष्ट रूप से उसे समझा दिया कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय है इसलिए अमेरिका की कोईं जरूरत है ही नहीं। 1990 के दशक में जब बिल क्लिंटन का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब उन्होंने भारत के महत्व को समझा और भारत विरोधी अपने स्टेट डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण नीति निर्धारकों को इधर से उधर करके भारत के प्राति सकारात्मक नजरिया रखने वालों को दक्षिण एशिया डेस्क पर तैनात किया। राबिन रापेल के स्थान पर इण्डरफर्थ की नियुक्ति के बाद अमेरिका ने अपनी कश्मीर नीति में व्यापक बदलाव किया। उसी वक्त से भारत के साथ अमेरिका के कईं बार खट्टे-मीठे संबंध बने बिगड़े किन्तु अमेरिका कश्मीर पर कोईं बयान देने से बचता रहा। वह ज्यादा से ज्यादा यही कहता रहा कि यदि भारत और पाकिस्तान दोनों चाहें तो वाशिगटन डीसी समझौता कराने की पहल कर सकता है किन्तु भारत के कड़े रुख को देखते हुए अमेरिका सार्वजनिक रूप से फटे में टांग अड़ाने से बचता रहा है। जहां तक अक्साईं चिन का सवाल है तो अमेरिका हमेशा चीन के खिलाफ रहा। 1962 में तो चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा ही तब कर दी थी जब अमेरिकी वायुसेना चुसूल हवाईं अड्डे पर स्थिति का आंकलन करने पंडित जवाहर लाल नेहरू के आग्राह पर आ गईं। यदि चीन उस वक्त युद्ध विराम की घोषणा न करता तो अमेरिका ब्रिटिश वायुसेना के साथ चीन के खिलाफ कार्रवाईं करने का पैसला कर ही चुका था। सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने समर्थक पाकिस्तान की भावनाओं को ठुकराकर लगातार पैसले क्यों ले रहा है? पहले वीजा की सूची से पाकिस्तान को बाहर करना और फिर पाकिस्तान के उत्पादों पर लगाए गए 19 प्रातिशत टैरिफ से एक प्रातिशत कम टैरिफ भारतीय उत्पादों पर लगाना और अब खुलकर भारत के कश्मीर विवाद में वूदना और समूचे जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना, इस बात का द्योतक है कि अब अमेरिका किसी भी हालत में भारत को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि अमेरिका भारत का सच्चा रणनीतिक सहयोगी है इसलिए भारत को चाहिए कि वह भी खुलकर वाशिगटन डीसी के हितों के प्राति संवेदनशीलता दिखाए। सच तो यह है कि इस वक्त ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों के कारण प्रावासी भारतीय अमेरिका में रिपब्लिकन पाटा से अत्याधिक नाराज हैं। जहां—जहां चुनाव हुए हैं, ट्रंप की कायंशैली की वजह से हर चुनाव में डेमोव्रेट हारे हैं। अब टेक्सास में सीनेट का उपचुनाव है और रिपब्लिकन पाटा की सीनेट में मात्र 4 सीट डेमोव्रेट से ज्यादा होने के कारण यह चुनाव ट्रंप प्राशासन के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत के प्रधानमंत्री की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के अवसर पर भारत-मलेशिया का संयुक्त वक्तव्य

(जीएनएस)।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो सेरी अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता और अटूट जन-संबंधों को दशार्ती है। इसने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने एवं विस्तार करने के लिए दोनों नेताओं की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

1957 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से, मलेशिया और भारत ने आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी की है। इस साझेदारी को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) का दर्जा दिया गया।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी का पुत्राजाया स्थित पदार्ना पुत्रा परिसर में औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद, दोनों नेताओं ने 8 फरवरी 2026 को आधिकारिक द्विपक्षीय बैठकें की और सीएसपी की पुष्टि की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यापक और सार्थक चर्चा की जिसमें राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, युवा आदान-प्रदान एवं जन-जन संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू शामिल थे। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक आधिकारिक भोज का आयोजन भी किया। उन्होंने संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई द्विपक्षीय दस्तावेजों के आदान-प्रदान को भी देखा।

दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध, सदियों पुराने संपर्क, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य, तथा मलेशिया में जीवंत भारतीय समुदाय की उपस्थिति, द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक अद्वितीय, मजबूत और स्थायी आधार का कार्य करते हैं और इसके बहुआयामी स्वरूप को समृद्ध करते हैं।

राजनीतिक सहयोग

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उच्च स्तरीय दौरों सहित नियमित संवाद एवं आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और समन्वय को मजबूत किया है। उन्होंने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर निरंतर जुड़ाव के महत्व को दोहराया। इस संदर्भ में, विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) और संयुक्त आयोग की बैठकें (जेसीएम) मलेशिया-भारत संबंधों को आधार प्रदान करने वाले प्रमुख मंच बने हुए हैं।

संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया और कहा कि इस प्रकार के जुड़ाव ने संस्थागत संबंधों को मजबूत किया है और आपसी समझ को गहरा किया है। उन्होंने हाल ही में 13-16 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) में मलेशियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, तन श्री दातो डॉ. जोहरी अब्दुल की भारत यात्रा पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, उन्होंने सितंबर 2025 में आसियान अंतर-संसदीय सभा (एआईपीए) की 46वीं महासभा के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा और 31 मई से 3 जून 2025 तक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा पर भी संतोष व्यक्त किया।

व्यापार और निवेश में सहयोग

मलेशिया भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक भागीदार मानते हुए, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की सराहना करता है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी पारस्परिक महत्व और रणनीतिक तालमेल पर आधारित है। दोनों नेताओं ने संतुलित सहयोग की भावना से प्रेरित होकर, व्यापार सुगमता बढ़ाने और सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

नेताओं ने मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (एमआईसीईसीए) और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने एआईटीआईजीए की चल रही समीक्षा का स्वागत किया ताकि इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी, व्यापार सुगम और वर्तमान वैश्विक व्यापार ढ यवस्थाओं के अनुरूप बनाया जा सके। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने की एमआईसीईसीए की क्षमता की सराहना की और इसके अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया।

भारत-मलेशिया संबंधों की नई सुबह संस्वृति, व्यापार और रणनीति की साझा यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी का यह मलेशिया दौरा इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया अपने ऐतिहासिक संबंधों को नईं ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। संस्वृति, व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग के जरिए यह साझेदारी आने वाले वर्षों में और गहरी हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आठ वर्षों बाद मलेशिया पहुँचना केवल एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि भारत-मलेशिया संबंधों में विश्वास, आत्मीयता और भविष्य की साझेदारी को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण क्षण है। वुआलालंपुर हवाईं अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना और उन्हें अपनी कार से कार्यव्रम स्थल तक ले जाना, दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी और आपसी सम्मान को दशार्ता है। यह दृश्य इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया के संबंध अब औपचारिकताओं से आगे बढ़ व्यक्तिगत भरोसे और गहरी समझ के स्तर पर पहुँच चुके हैं।

भारत और मलेशिया के रिश्तों की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। सदियों पहले समुद्री मार्गो के जरिए भारतीय व्यापारी, विद्वान और सांस्वृतिक परंपराएँ मलाया प्रायद्वीप तक पहुँचीं। मसाले, नारियल, चाय और वस्त्रों के व्यापार के साथ-साथ भाषा, धर्म और संस्वृति का आदान-प्रदान भी हुआ। आज भी मलेशिया की संस्वृति में भारतीय प्रभाव साफ दिखाईं देता है, विशेषकर तमिल समुदाय के माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि वुआलालंपुर और कोच्चि में स्वाद एक जैसा लगता है, केवल भोजन का वर्णन नहीं है, बल्कि उस साझा सांस्वृतिक विरासत की ओर संकेत है जो दोनों देशों को जोड़ती है।

राजनयिक स्तर पर भारत और मलेशिया के संबंध मलेशिया की स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित हो गए थे। समय के साथ इन रिश्तों ने मजबूती हासिल की और दोनों देशों ने आपसी विश्वास के आधार पर सहयोग के नए आयाम जोड़े।

वर्ष 2015 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और बाद में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। इसका अर्थ यह है कि भारत और मलेशिया केवल व्यापार या राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्व जैसे दीर्घकालिक और संवेदनशील क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं।

मलेशिया में लगभग उनतीस लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक हैं। यह समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभाता है।

भारतीय मूल के नागरिक मलेशिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा और संस्वृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं भारत के लिए यह समुदाय भावनात्मक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यही कारण है कि हर भारतीय प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा में प्रवासी भारतीय समुदाय विशेष वेंद्र में रहता है।

व्यापार भारत-मलेशिया संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है।

मलेशिया भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, हालांकि भारत को वुछ वर्षों से व्यापार घाटे की चुनौती का सामना करना पड़ा है। भारत मलेशिया से मुख्य रूप से खाद्य तेल आयात करता है, विशेष रूप से पाम तेल, जो भारत की घरेलू आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा भारत मलेशिया से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्धचालक से जुड़े पुज्रे, रसायन, पेट्रो रसायन उत्पाद, रबर और लकड़ी से बने सामान भी आयात करता है।

दूसरी ओर भारत मलेशिया को पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, वाहन, इस्पात, रसायन, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं निर्यात करता है। भारतीय दवा उद्योग मलेशिया में अच्छी पहचान रखता है, क्योंकि भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ वहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसी तरह भारतीय तकनीकी वंपनियां मलेशिया के डिजिटल विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा की जा रही है, ताकि भारतीय उद्योगों और मलेशियाईं भागीदारों दोनों को समान लाभ मिल सके।

मलेशिया से भारत को कच्चे माल और रणनीतिक आपरूति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।

अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मलेशिया की वैश्विक भूमिका भारत के लिए खास मायने रखती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया आपरूति श्रृंखला को विविध बनाने की दिशा में आगे ब. रही है। वहीं मलेशिया के लिए भारत एक विशाल बाजार, तेज़ी से बढ़ अर्थव्यवस्था और निवेश के असीम अवसरों वाला देश है।

भारत की जनसंख्या, डिजिटल चा और निर्माण क्षमता मलेशियाईं वंपनियों को आर्कषित करती है।

रणनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर भी भारत और मलेशिया एकदूसरे के लिए बेहद अहम हैं।

मलक्का जलडमरूमध्य विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गो में से एक है, जहाँ से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है।

भारत की हिद-प्रशांत दृष्टि और मलेशिया की क्षेत्रीय भूमिका एकदूसरे के पूरक हैं। नौसैनिक सहयोग और रक्षा संवाद के माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे रहे हैं। डिजिटल और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में सहयोग भारत-मलेशिया संबंधों को भविष्य की दिशा दे रहा है। भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और मलेशिया में इसके विस्तार से न केवल

पीड़ा की धरती पर आशा का वृक्षः बाबा आमटे

कुछ लोग जन्म लेकर नहीं,बल्कि अपने कर्मो से अमर बनते हैं। वे समय की सीमाओं को लांघकर समाज की आत्मा में स्थायी स्थान बना लेते हैं। बाबा आमटे ऐसे ही विरले व्यक्तित्व थे, जिनका संपूर्ण जीवन करुणा, साहस और सेवा का उज्ज्वल प्रतीक बन गया। 9फरवरी 2008 को भले ही उनकी देह नश्वरता में विलीन हो गईं हो,परंतु उनके विचार आज भी असंख्य जीवनों को दिशा और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वे केवल एक समाजसेवक नहीं, बल्कि मानवीय चेतना की सजीव अभिव्यत्ति थे, जिन्होंने पीड़ा को संबल और दुर्बलता को आत्मविश्वास में बदल दिया। उनके लिए सेवा कोईं औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आत्मा की तपस्या थी। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि स्थायी परिवर्तन बाहरी सहायता से नहीं,बल्कि अंतर्मन की जागृति से उत्पन्न होता है। 26 दिसंबर 1914को महाराष्ट्र के हिगणघाट, वर्धा में जन्मे मुरलीधर देवीदास आमटे का प्रारंभिक जीवन वैभव और सुविधा से सुसज्जित था।

संपन्न परिवार में पले-बढ़े बाबा आमटे ने बचपन से ही ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और आधुनिक जीवनशैली का अनुभव किया। आकर्षक वस्त्र, तेज रफ्तार वाहन और सामाजिक सम्मान उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे।

किंतु इस भौतिक चमक-दमक के पीछे उनके मन में एक गहन बेचैनी निरंतर करवट लेती रहती थी। वे जीवन को केवल सुख-साधनों का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य से जोड़ना चाहते थे। यही आंतरिक मंथन धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व को रूपांतरित करता गया और उन्हें आत्मवेंद्रित सोच से निकालकर सामाजिक दायित्व की ओर अग्रसर करता चला गया। शिक्षा और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बाबा आमटे ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। नागपुर से बी.ए. और एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त कर वे एक सक्षम और प्रतिष्ठित वकील बने। न्यायालयों में कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि कानून की पहुंच अक्सर निर्बल और वंचित वर्ग तक नहीं हो पाती। निर्णय तो होते थे, परंतु पीड़ितों की पीड़ा अनसुनी रह जाती थी। इसी काल में एक उपेक्षित वुष्ठ रोगी को असहाय अवस्था में देखकर उनका अंतःकरण विचलित हो उठा। समाज द्वारा ठुकराए गए उस मानव की दुर्दशा ने उनकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। उसी क्षण उन्होंने दृढ़ निाय किया कि वे अपना संपूर्ण जीवन उन लोगों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे, जिन्हें समाज ने उपेक्षा और तिरस्कार के अंधकार में छोड़ दिया है। जब संकल्प सच्चा हो और उद्देश्य पवित्र,तब वह इतिहास का

कौन हैं रूबल नागी? बला की खूबसूरत महिला ने जीता 'ग्लोबल टीचर प्राइज', रातोंरात बन गई करोड़पति

(जीएनएस)।

भारत की जानी-मानी कलाकार और सोशल वर्कर रूबल नागी ने शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है। रूबल नागी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित 'ग्लोबल टीचर प्राइज' से दुबई में सम्मानित किया गया है।

इस अवार्ड के बाद रूबल नागी लगातार सुर्खियों में हैं। जानिए कौन है रूबल नागी और उन्होंने ऐसी क्या पहल की है कि जिसकी बदौलत उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? लोबल टीचर प्राइज पाकर रूबल नागी रातोंरात बनीं करोड़पति

दुबई में आयोजित World Government Summit के दौरान रूबल नागी की दो दशक लंबी सामाजिक यात्रा को दुनिया ने सराहा। GEMS Educationf Global Teacher Prize जिसे शिक्षा जगत का "नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, इसके तहत रूबल नागी को $1 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि मिली है।

139 देशों को पछाड़ कर रूबक नागी ने जीता खिताब

ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए 139 देशों से 5,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से रूबल नागी का चयन किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और वर्ल्ड फाउंडेशन के फांडडर सनी वर्की द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा UNESCO के सहयोग से दिया जाता है। कौन हैं रूबल नागी?

रूबल नागी मुंबई की रहने वाली एक प्रसिद्ध कलाकार, म्यूरलिस्ट और सोशल वर्क हैं। इनका जन्म जम्मू-कश्मीर में हुआ और उन्होंने लंदन के SlÔde School of Fine Art से आर्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई की। शुरूआत में वह अपनी मूर्तिकला और भित्ति चित्रों के लिए पहचानी गईं।

लेकिन बाद में रूबल ने कला को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाते हुए "क्लासरूम" की पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह से नया रूप दिया। इसी सोच के साथ उन्होंने Rouble Nagi Art FoundÔtion (RNAF) की स्थापना की।

नेपाल के सामने इंग्लैंड को आया पसीना, अंतिम गेंद तक चले मैच में इंग्लिश टीम ने 4 रनों से जीता मुकाबला

T20 World Cup 2026 में आज क्रिकेट प्रशंसकों को वह मुकाबला देखने को मिला, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया यह मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जहां जीत और हार का फैसला अंतिम गेंद तक लटका रहा। एक तरफ अनुभव से भरी विश्व विजेता इंग्लैंड की टीम थी, तो दूसरी तरफ अपने जज्बे से इतिहास रचने को बेताब नेपाल के जांबाज।

पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की सांसें थमी रहीं। नेपाल ने जिस तरह से दिग्गज इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया, उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट में अब कोई भी टीम 'छोटी' नहीं रही। इस बेहद करीबी मुकाबले ने टूनार्मेंट में रोमांच का नया तड़का लगा दिया है।

इंग्लैंड की पारी, बेथेल और ब्रूक का धमाका

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई थी। लेकिन इसके बाद मध्यक्रम ने मोर्चा संभाला। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल थे।

कप्तान हैरी ब्रूक ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 32 गेंदों पर 53 रनों की कप्तानी पारी खेली। अंत में विल जैक्स ने मोर्चा संभाला और महज 18 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर इंग्लैंड के स्कोर को 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन तक पहुंचाया।

नेपाल का पलटवार, रोहित पौडेल और दिपेंद्र की जुझारू पारी

185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। सलामी बल्लेबाज कुशल भुर्तेल ने टीम को तेज शुरूआत दी।

कौन हैं विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा? पाकिस्तान में खेलने के लिए किया रजिस्ट्रेशन? सामने आया सच

(जीएनएस)।

सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर ने क्रिकेट और बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है। मशहूर फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ('12th फेल' फेम) के बेटे अग्नि देव चोपड़ा का नाम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 की ऑक्शन लिस्ट में देखे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब इस युवा क्रिकेटर ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की एक कथित ऑक्शन लिस्ट वायरल हुई। इस लिस्ट में अग्नि देव चोपड़ा का नाम 822वें नंबर पर दर्ज था। उन्हें वरअ (अमेरिका) के खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया था और उनकी बेस प्राइस करीब 6 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR 600,000) बताई गई थी। जैसे ही यह खबर फैली, नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

अग्नि चोपड़ा ने दी सफाई

विवाद बढ़ता देख अग्नि देव चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे नाम से एक

टूनार्मेंट (PSL) को लेकर गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने PSL के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मेरा पूरा ध्यान इस समय अमेरिका (USA) में अपने क्रिकेट करियर और भविष्य के लक्ष्यों पर है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।

कौन हैं अग्नि देव चोपड़ा? (क्रिकेट करियर और रिकॉर्ड्स)

अग्नि देव चोपड़ा केवल एक स्टार किड नहीं हैं, बल्कि एक क्रिकेटर भी हैं। उनके बारे में कुछ खास बातें शायद कम लोग जानते हैं. अग्नि ने भारत में मिजोरम के लिए खेलते हुए अपने पहले 4 प्रथम श्रेणी (First-Class) मैचों में लगातार 5 शतक जड़कर इतिहास रचा था। उन्होंने 11 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 95 की औसत से 1804 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक शामिल हैं।

USA कनेक्शन

अग्नि का जन्म अमेरिका के डेट्रायट में हुआ था, इसलिए उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। बीसीसीआई के नियमों के कारण उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट छोड़कर अब वरअ से खेलने का फैसला किया है। वे मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में MI New York टीम का हिस्सा हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध तनावपूर्ण हैं और कोई भी भारतीय खिलाड़ी PSL नहीं खेलता, इसलिए अग्नि का नाम लिस्ट में आना चौंकाने वाला था। हालांकि, अग्नि अमेरिकी नागरिक हैं, फिर भी उनकी भारतीय जड़ों के कारण इस खबर ने तूल पकड़ा।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

खुशखबरी, बेंगलुरू में नम्मा मेट्रो का नहीं बढ़ेगा किराया, आखिर क्यों वापस लिया गया फैसला?

(जीएनएस)।

बेंगलुरू में नम्मा मेट्रो पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने अपनी एनुअल ऑटोमैटिक फेयर रिविजन स्कीम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। याद रहे ये 9 फरवरी (सोमवार) से लागू होने वाली थी। इस स्कीम के तहत शहर में सभी लाइनों की नम्मा मेट्रो के किराए में 5 फीसदी की बढोत्तरी होने वाली थी।

लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के फैसले पर जनता के तीव्र विरोध और राज्य के कांग्रेस नेतृत्व तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीखी राजनीतिक तकरार के बाद ये मेट्रो के टिकट का किराया बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है।

क्या नहीं बढ़ेगा मेट्रो का किराया?

BMRCL ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुष्टि की है कि अगले आदेश तक मौजूदा किराया ही लागू रहेगा। निगम निदेशक मंडल संशोधित मूल्य स्लैब की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय करेगा।कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में कहा, "5 फरवरी 2026 की मीडिया विज्ञप्ति में 9 फरवरी 2026 से वार्षिक

किराया संशोधन की घोषणा की गई थी, उसे अब अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। संशोधित किराए पर निर्णय बोर्ड की समीक्षा के बाद ही घोषित किया जाएगा।"

क्यों मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया वापस?

यह विवाद तब गरमाया जब बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से याचिका करके उन्होंने इस किराया वृद्धि को रुकवाया है। सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रशासन पर "कमजोर वित्तीय स्थिति" की भरपाई के लिए किराया बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने कांग्रेस की "जनता-लुभावन गारंटी योजनाओं" का परिणाम बताया।

सांसद ने किराया निर्धारण समिति (FFC) की रिपोर्ट में "mathematical errors" का भी जिक्र किया। उन्होंने तर्क दिया कि बेंगलुरु में पहले से ही भारत का सबसे महंगा मेट्रो सिस्टम है, और किसी भी अतिरिक्त वृद्धि से मध्यम वर्ग के लिए सार्वजनिक परिवहन बहुत महंगा और दुर्गम हो जाएगा।

जवाब में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाजपा के आरोपों को "जनता को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास" बताते हुए जिम्मेदारी से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत किराए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र समिति तय करती है, राज्य का इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं।

BMRCL ने क्या कहा?

डी.के. शिवकुमार ने जानकारी दी कि BMRCL बोर्ड ने उनसे इस संशोधन पर कोई परामर्श नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति के अध्यक्ष एक केंद्रीय सरकारी सचिव हैं, जिससे विवाद का केंद्र प्रभावी रूप से केंद्र सरकार की ओर चला जाता है।

इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, कल होने वाली BMRCL बोर्ड की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा का आग्रह है कि राज्य लागतों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक नई किराया निर्धारण समिति का औपचारिक रूप से अनुरोध करे। वहीं, कांग्रेस नेतृत्व का मत है कि मूल्य वृद्धि का प्राथमिक चालक वास्तव में केंद्रीय ढांचा ही है।

बेंगलुरु के लाखों दैनिक यात्रियों को फिलहाल अस्थायी राहत मिली है, हालाँकि "नम्मा मेट्रो" की दीर्घकालिक वहनीयता शहर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

'सब्सिडी अमेरिका की, जोखिम भारत का' – भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जीतू पटवारी का तीखा हमला

(जीएनएस)।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने इस समझौते को सीधे तौर पर किसान विरोधी बताते हुए कहा कि यह ऐसा करार है जिसमें सब्सिडी अमेरिका की है और जोखिम भारतीय किसानों पर डाला जा रहा है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री" करार देते हुए आरोप लगाया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं और देश के किसानों के हितों से समझौता किया गया है।

जीतू पटवारी ने कहा कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि कई छिपे हुए समझौतों का पैकेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील अमेरिका में अडानी समूह से जुड़े मामलों को दबाने का प्रयास है, रूस से तेल नहीं खरीदने के अमेरिकी दबाव का हिस्सा है और उन मुद्दों से ध्यान हटाने का जरिया भी है, जिनमें प्रधानमंत्री का नाम एप्सटीन फाइल्स में सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर देश के अन्नदाता की कीमत पर कोई भी सौदा स्वीकार्य नहीं हो सकता।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित बैठक और दिए गए बयानों के जरिए किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक सरकार ने उत्पाद-वार टैरिफ संरचना, नॉन-टैरिफ बैरियर की शर्तें और इस समझौते की आधिकारिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को मंच से दिए गए भाषण नहीं, बल्कि लिखित और ठोस गारंटी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

जीतू पटवारी ने भारत और अमेरिका की कृषि संरचना में भारी

असमानता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अमेरिका में औसत कृषि जोत 440 से 450 एकड़ के आसपास है, जबकि भारत में यह मात्र 2 से 2.5 एकड़ है। अमेरिका में केवल 1 से 2 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, जबकि भारत में बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसी असमान परिस्थितियों में यदि भारतीय किसानों को सब्सिडी-समर्थित अमेरिकी किसानों से खुली प्रतिस्पर्धा में उतारा जाएगा, तो इसका परिणाम भारतीय कृषि के लिए विनाशकारी होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका में "फार्म बिल" और अन्य योजनाओं के तहत किसानों को व्यापक सब्सिडी और वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। भारत में जहां औसतन एक किसान को लगभग 14 हजार रुपये प्रतिवर्ष की प्रत्यक्ष सहायता मिलती है, वहीं अमेरिकी किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं अधिक आर्थिक समर्थन मिलता है। उन्होंने दिसंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन द्वारा फसल क्षति के लिए अरबों डॉलर की सहायता स्वीकृत किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां संकट के समय भी किसान पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जबकि भारत का किसान हर झटके में सबसे पहले टूटता है।

जीतू पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि नॉन-टैरिफ बैरियर कम किए जाते हैं या बाजार को चरणबद्ध तरीके से खोला जाता है, तो सब्सिडी-समर्थित सस्ता अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश करेगा। उन्होंने सवाल किया कि दो एकड़ जमीन वाला भारतीय किसान 450 एकड़ वाले सब्सिडी-संरक्षित अमेरिकी किसान से कैसे मुकाबला करेगा। यह असमान प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर भारतीय किसानों की आय और अस्तित्व पर हमला है।

उन्होंने सरकार की नीतियों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि मक्का का आयात नहीं होगा, लेकिन पोल्ट्री फीड या एनिमल फीड के नाम पर मक्का आधारित प्रोसेस्ड उत्पाद यदि आयात होते हैं, तो इसका सीधा असर देश के मक्का किसानों पर पड़ेगा। इसी तरह यदि सोयाबीन का आयात नहीं होगा, लेकिन सोयाबीन तेल आयात किया जाएगा, तो मध्यप्रदेश के लाखों सोयाबीन उत्पादक किसानों की आय दबाव में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के हितों के विपरीत है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कृषि संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस समय कृषि उत्पादों पर औसतन 30 से 60 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया गया था और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह शुल्क 60 से 100 प्रतिशत तक रखा गया, ताकि विदेशी डंपिंग से भारतीय किसानों की रक्षा की जा सके। उन्होंने सवाल किया कि यदि आज 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत तक टैरिफ कम किया जा रहा है, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि भारी असमानता के बावजूद भारतीय किसान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा।

जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा कि क्या वे लिखित रूप से यह गारंटी देंगे कि सोयाबीन तेल आयात से किसानों को मिलने वाला मूल्य प्रभावित नहीं होगा, पोल्ट्री फीड आयात से मक्का किसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। उन्होंने मांग की कि उत्पाद-वार टैरिफ कटौती की विस्तृत सूची, नॉन-टैरिफ प्रावधानों का पूरा विवरण और इस ट्रेड डील की आधिकारिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए।

अंत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस व्यापार विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अन्नदाता की कीमत पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिस दिन भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम रूप से लागू होगी, उस दिन मध्यप्रदेश का किसान उसके विरोध में सड़कों पर उतरेगा और कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में एकजुट होकर आंदोलन और जाम करेगी।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ऐतिहासिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है- श्री शिवराज सिंह चौहान

भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं

ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का प्रतीक

अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों को शून्य शुल्क पर मिलेगा बाजार

भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद ट्रेड डील में शामिल नहीं

ट्रेड डील किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को देगा नई उड़ान

आत्मनिर्भर-विकसित भारत के निर्माण में ऐसे सभी समझौते मील के पत्थर

(जीएनएस)।

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति और नई ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। ट्रेड डील केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। यह डील भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उसे नई दिशा प्रदान करेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। यह डील दुनिया को संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। हम आत्मविश्वास के साथ देश के हित में निर्णय लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर संतुलित और सकारात्मक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते, बल्कि संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में उभर रहा है।

डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यह ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। डिप्लोमेसी का अर्थ है राष्ट्र प्रथम, और इस समझौते में भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखे गए हैं। डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम यह डील उसके लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। डिग्निटी का मतलब है किसान की गरिमा, और मुझे गर्व है कि इस समझौते में किसान की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों को लेकर

देश के मन में जो भी चिंताएं थीं, उनका इस ट्रेड डील में समाधान किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह डील केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नए अवसरों का द्वार भी खोलती है। यह ट्रेड डील हमारे कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नए अवसर प्रदान करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है।

अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में यह छूट नहीं मिली है। भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कृषि क्षेत्र के कई उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है। कई कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ पहले 50 प्रतिशत तक था, उसे अमेरिका ने घटाकर शून्य कर दिया है। इसमें मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति वैक्स, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम और कुछ अनाज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। मसाला निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इस ट्रेड डील के बाद हमारे मसालों को अमेरिका में भी नया और बड़ा बाजार मिलेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत पहले से ही मसालों के वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति रखता है। दुनिया भर के करीब 200 स्थानों पर भारत मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात करता है। इस समझौते से मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय कृषि बाजार में आते हैं, तो उन्हें टैरिफ देना होगा। हमारे किसानों को पूरी छूट और पूरा संरक्षण प्राप्त है। यही इस ट्रेड डील की सबसे बड़ी ताकत है।

सभी संवेदनशील वस्तुएं समझौते से बाहर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और ऐसा कोई भी उत्पाद समझौते में शामिल नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान हो। सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता देश के प्रमुख अनाजों को लेकर थी। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहने चाहिए और मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो सभी पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल और डेयरी उत्पादों के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी और मिक्स्ड डिब्बाबंद सब्जियां भारत नहीं आएंगी। डेयरी उत्पादों को लेकर भी उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों में लिक्विड मिल्क, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज, इनमें से किसी को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी के अलावा भारत, अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब साफ है हमारे मसाले और हमारे किसान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

किसान, महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और खासकर युवा वर्ग को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हमारे कई सेक्टर जैसे टेक्सटाइल में अब प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमारा टैरिफ काफी कम होकर करीब 18 प्रतिशत रह गया है। इससे टेक्सटाइल निर्यात को नई गति और नई दिशा मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात का सीधा लाभ किसानों को भी मिलेगा। टेक्सटाइल का मतलब है किसानों को फायदा, खासकर कपास उत्पादक किसानों को। इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ढेर सारे नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का जीवन भी इस समझौते से समृद्ध होगा, क्योंकि कई उत्पादों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह डील उनके परिश्रम और हुनर को वैश्विक पहचान दिलाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक नौ एफटीए हो चुके हैं। अमेरिका के अलावा यूएई के 27 देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ एफटीए किया जा चुका है और अन्य देशों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इन सभी समझौतों का व्यापक लाभ देश को मिलेगा। इन डील्स का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निर्यातकों और निर्माताओं को होने वाला है। इसी के माध्यम से हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में यह समझौता और ऐसे सभी समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

बेलगावी हवाई अड्डे के पास मेसर्स रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षण विमान की आपातकालीन लैंडिंग

विमान का प्रकारः सेसना 172, पंजीकरण संख्याः वीटी-ईयूसी

(जीएनएस)।

आज, रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के सेसना 172 विमान (वीटी-ईयूसी) को कलबुर्गी से बेलगावी रूट पर उड़ान भरते समय, ईंधन की कमी के कारण विजयपुरा के पास एक खुले मैदान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। आपातकालीन लैंडिंग का स्थान बेलगावी हवाई अड्डे से 50 से 70 किलोमीटर दूर है। विमान में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक प्रशिक्षु पायलट सवार थे। दोनों यात्री सुरक्षित हैं। टक्कर के कारण विमान क्षतिग्रस्त हो गया है।

1. संगठन संबंधी जानकारीः

मेसर्स रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग

एकेडमी एक डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) है, अनुमोदन संख्या 01/2020।

प्रारंभिक एफटीओ अनुमोदन 23/07/2020 को जारी किया गया था।

एफटीओ का अंतिम नवीनीकरण 23/07/2025 को हुआ था और यह 22/07/2030 तक वैध है।

बेड़े में विमानों की संख्याः 48 विमान

2. विमान का विवरण दिनांक 08/02/2026 के अनुसारः

निर्माण का वर्षः 1975

सी ऑफ आर जारी करने की तिथिः 23/05/2023 (रेड बर्ड एफटीओ के साथ)।

प्रमाणन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथिः 20/09/2023

एआरसी जारी करने की तिथिः 01/08/2025, वैधता अवधिः 03/08/2026

समाचार प्रकाशित होने के बाद से समय (टीएसएन): 17512:40

3. इंजन विवरण

इंजन का प्रकारः लाइकमिंग ड320-ई2डी

इंजन घंटेः 802:10 घंटे

4. क्रू जानकारी

पीआईसी (फ्लाइट इंस्ट्रक्टर): सीपीएल धारक

अंतिम चिकित्सा जांच की तिथिः 18.03.2025 (19.03.2026 तक वैध)

उड़ान का समयः 734 घंटे

पिछली सूचना संचार/दक्षता जांच तिथिः 25.07.2025

आगे की जांच डीजीसीए/एएआईबी द्वारा की जाएगी।

दिल्ली में अब 50 हजार हाईटेक सीसीटीवी से बदलेगी महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर

(जीएनएस)।

राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहर भर में करीब 50,000 नए हाईटेक उउळश कैमरे लगाने का फैसला किया है।

यह कदम उन इलाकों पर फोकस करेगा, जहां अंधेरा रहता है या फिर सुरक्षा को लेकर पहले शिकायतें सामने आती रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 646.6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

यह योजना क्यों है खास?

यह प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत राजधानी में 24 घंटे निगरानी वाली मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 'Women Safety in Delhi' योजना के तहत शुरूआती तौर पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि लगातार निगरानी से अपराध पर अंकुश लगेगा और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा।

कहां-कहां लगाए जाएंगे कैमरे?

पीडब्ल्यूडी के शुरूआती आकलन के अनुसार, दिल्ली के उन सभी इलाकों को चुना गया है जहां रोशनी कम रहती है या फिर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है। इन जगहों पर करीब 49,900 चार-मेगापिक्सल वढ बुलेट CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे रळदउ मानकों के अनुसार होंगे और हर कैमरे में 512GB का लोकल स्टोरेज दिया जाएगा। इन स्थानों का चयन महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली पुलिस के इनपुट के आधार पर किया गया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब फाइलों में नहीं अटकेगा विकास! MCD आयुक्त को 50 करोड़ तक मंजूरी का अधिकार

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब फाइलों में नहीं अटकेगा विकास! MCD आयुक्त को 50 करोड़ तक मंजूरी का अधिकार

रात में गाड़ियों पर कैसे रहेगी नजर?

रात के समय निगरानी और वाहनों की पहचान को और मजबूत करने के लिए 100 हाई-रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी अठढफ कैमरे भी लगाए जाएंगे। इनमें इन्फ्रारेड विजन होगा, जो 100 मीटर की दूरी से भी नंबर प्लेट कैप्चर कर सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक, इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ-साथ किसी भी वारदात के बाद जांच में बड़ी मदद मिलेगी।

हर पोल पर कितने कैमरे लगेंगे?

इस योजना के तहत शहर में करीब 17,000 आठ-मीटर ऊंचे पोल लगाए जाएंगे। हर पोल पर दो से तीन बुलेट कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं ANPR कैमरों के लिए 100 अलग पोल लगाए जाएंगे, जिन पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी होगा। इससे कैमरों की सुरक्षा और टिकाऊपन दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे।

बिजली और बैकअप का क्या इंतजाम है?

जहां बिजली की लाइन उपलब्ध नहीं है, वहां करीब 5,000 सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाएंगे। इनमें लिथियम-आयन बैटरी होगी, जो कम से कम 14 घंटे का बैकअप देगी। इसके अलावा 12,100 वढर यूनिट्स भी लगेंगी, जो करीब 30 मिनट का बैकअप देंगी। कैमरों से आने वाले डेटा के लिए फायरवॉल से सुरक्षित स्टोरेज सिस्टम और एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है।

कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?

इस प्रोजेक्ट का खर्च कई सालों में किया जाएगा। 2025-26 में 50 करोड़ रुपये, 2026-27 में 300 करोड़ रुपये और बाकी राशि 2031-32 तक किस्तों में खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती देगा और राजधानी को और सुरक्षित बनाएगा।

प्रधानमंत्री ने मलेशिया में प्रवासी भारतीयों के प्रमुख सदस्यों के साथ संवाद किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री ने मलेशिया में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख सदस्यों और नेताओं के साथ संवाद किया। इन गणमान्य व्यक्तियों में मंत्री, सीनेटर, सांसद और आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी-आईएनए) के वेटरन शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में शामिल थेः मिनिस्टर ऑफ डिजिटल तुआन गोबिंद सिंह देव, मानव संसाधन मंत्री दातो श्री रमणन रामकृष्णन, डिप्टी मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट एम. कुलसेगरन, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ नेशनल यूनिटी आर. युनेस्वरन एवं अन्य।

प्रधानमंत्री ने मलेशिया की प्रगति और विकास में तथा भारत-मलेशिया संबंधों को सुदृढ़ करने में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। भारतीय मूल के नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारत-मलेशिया संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में की गई पहलों के प्रति अपनी

गहरी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने भारत के परिवर्तनकारी बदलाव के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और विभिन्न योजनाओं की भी सराहना की।

भारतीय मूल के नेताओं ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों हेतु प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिनमें शामिल हैंः (i) मलेशिया में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय; (ii) यूनिवर्सिटी मलाया में तिरुवल्लुवर सेंटर स्थापित करने की घोषणा; (iii) तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप की शुरूआत; (iv) मलेशिया में रहने वाले छठी (6वीं) पीढ़ी के भारतीय मूल के लोगों के लिए ओसीआई कार्ड का विस्तार; और (v) मलेशियाई भारतीय छात्रों के लाभ के लिए इंडियन स्कॉलरशिप ट्रस्ट फंड (आईएसटीएफ) में 3 मिलियन मलेशियाई रिंगिट (आरएम) की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करना।

प्रधानमंत्री ने आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी-आईएनए) की बालक सेना के वयोवृद्ध सदस्य दातो जयराज राजा राव और नेताजी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। उन्होंने आईएनए और उसके सैनिकों के अविस्मरणीय साहस और बलिदान की गहरी सराहना की। उन्होंने एक सशक्त और आधुनिक भारत के निर्माण के नेताजी के विजन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

टीटी नगर में माइनिंग विभाग की महिला कर्मचारी को घर में ही बंधक बनाकर लूट

(जीएनएस)।

भोपाल के टीटी नगर इलाके में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। माइनिंग विभाग में असिस्टेंट ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत 28 वर्षीय अर्चना वर्मा को उनके ही घर में बंधक बनाकर लूट लिया गया।

आरोपी ने चाकू की नोक पर महिला को धमकाकर घर में मौजूद 1.68 लाख रुपये कैश, एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन और अन्य सामान सहित कुल करीब सवा तीन लाख रुपये का माल लूट लिया।

आरोपी महिला की नौकरानी का बेटा आशीष उर्फ गोली रायकवार और उसका 15 वर्षीय नाबालिग मौसेरा भाई है। पुलिस ने रविवार तड़के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई अधिकांश रकम व सामान बरामद कर लिया है।

घटना का पूरा विवरण

अर्चना वर्मा 98 क्वार्टर टीटी नगर में रहती हैं। उनके पिता एक निजी

कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि मां की बीमारी के चलते कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। अर्चना घर की इकलौती कमाने वाली सदस्य हैं। घर के छोटे-मोटे काम के लिए उन्होंने एक महिला (मेड) को रखा हुआ था। इसी मेड का बेटा आशीष उर्फ गोली रायकवार है। आशीष हाल ही में हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल से छूटा था।

आशीष अर्चना के घर में पहले से ही छोटे-मोटे काम करता था। उसे घर का लेआउट, सामान कहां रखा है और कब कौन घर पर होता है-यह सब पता था। उसने अपने 15 साल के मौसेरे भाई के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। शनिवार शाम करीब 7 बजे आशीष और उसका नाबालिग साथी काम के बहाने घर पहुंचे। गेट खुलते ही दोनों ने धक्का देकर अंदर दाखिल हो गए।

चाकू की नोक पर अर्चना को कमरे में ले जाकर बंधक बना लिया। उन्होंने महिला से पूछा कि कैश कहां रखा है, मोबाइल कहां है। करीब 15 मिनट के भीतर बदमाशों ने अलमारी और अन्य जगहों से 1.68 लाख रुपये कैश, एप्पल आईफोन और अन्य सामान लूट लिया। लूटपाट के बाद दोनों फरार हो गए।

आरोपी का खुलासाः "लोन रिकवरी के लिए फोन आ रहे थे"

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आशीष ने बताया कि उसका समूह का लोन था। रिकवरी के लिए लगातार फोन आ रहे थे। इसी दबाव में उसने लूट की वारदात की। बची रकम से वह नई बाइक खरीदने और अपने शौक पूरे करने वाला था। नाबालिग साथी को भी उसने साथ लिया क्योंकि वह घर की पूरी जानकारी रखता था।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही टीटी नगर थाना पुलिस सक्रिय हुई। टीआई गौरव सिंह के नेतृत्व में टीम ने रविवार तड़के ही दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया। कार्रवाई में लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आशीष उर्फ गोली रायकवार पहले से ही हत्या के प्रयास के मामले में जेल में था और हाल ही में छूटा था। उसके खिलाफ कई पुराने मामले भी दर्ज हैं। नाबालिग साथी के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

घटना से महिलाओं में दहशत

टीटी नगर जैसे मध्यमवर्गीय इलाके में घर में ही लूट की यह घटना महिलाओं में दहशत फैला रही है। अर्चना वर्मा ने बताया कि उन्हें पहले कभी संदेह नहीं हुआ क्योंकि आशीष घर में आता-जाता था। अब वे कह रही हैं कि घरेलू नौकर रखते समय पूरी जांच जरूरी है। पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी है और घरेलू नौकर रखने वालों से सतर्क रहने की अपील की है।

समाज में चर्चा

यह घटना एक बार फिर घरेलू नौकरों और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जरूरत पर सवाल उठा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि घर में काम करने वाले लोगों की पहचान और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य होना चाहिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

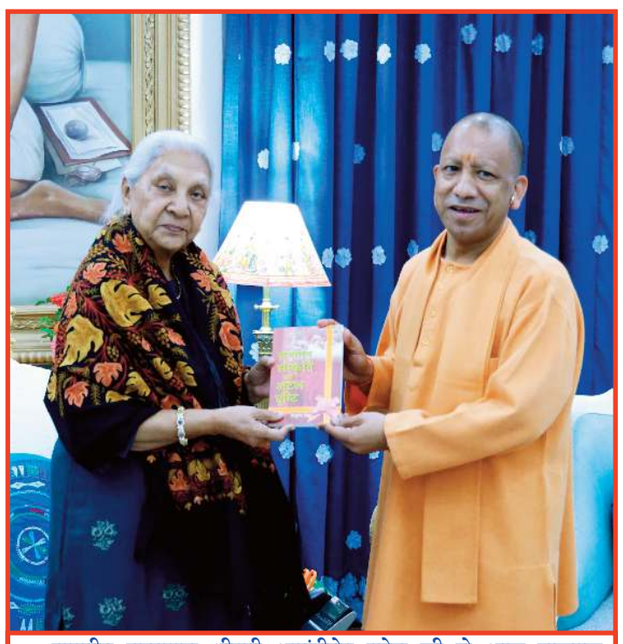

माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से आज लखनऊ स्थित जन भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 'सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि' पुस्तक भेंट की।

केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में बाढ़ के पूवार्नुमान और बाढ़ प्रबंधन संबंधी डीपीआर पर हितधारकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा

(जीएनएस)।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 9 फरवरी 2026 (सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक) को सीडब्ल्यूसी पुस्तकालय भवन, आरके पुरम, नई दिल्ली स्थित सभागार में बाढ़ पूवार्नुमान सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन डीपीआर की तैयारी एवं मूल्यांकन के लिए दिशानिदेर्शों पर एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वीएल कांता राव, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री अनुपम प्रसाद, केंद्रीय जल आयोग के सदस्यों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर सुबह 10:00 बजे से शुरू होने वाली कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।

कार्यशाला के दौरान, सभी हितधारकों के साथ सीडब्ल्यूसी की मौजूदा सेवाओं और नई पहलों को साझा करने और बाढ़ के पूवार्नुमान, तैयारी और बाढ़ प्रबंधन योजना में केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न संबंधित केंद्रीय संगठनों के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा सीडब्ल्यूसी की पूवार्नुमान और निर्णय-सहायता सेवाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित राज्य सरकारों को बाढ़ की पूवार्नुमान गतिविधियों में अपनी पहलों और सीडब्ल्यूसी सेवाओं के साथ तालमेल बनाने के विकल्पों को साझा करने का अवसर दिया जाएगा।

सुबह के तकनीकी सत्रों में सीडब्ल्यूसी की बाढ़ की पूवार्नुमान क्षमताओं के बारे में बताया जाएगा। इनमें अल्पकालिक और सात दिवसीय परामर्श पूवार्नुमान, जलमग्नता पूवार्नुमान, एकीकृत जलाशय संचालन सहायता, जीएलओएफ निगरानी और एआई/एमएल अनुप्रयोगों जैसी नई पहलें, आईएमडी से विस्तारित अवधि के वर्षा पूवार्नुमानों का उपयोग और अचानक बाढ़ पूवार्नुमान शामिल हैं। राज्य सरकारें बाढ़ के पूवार्नुमान और सीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय में अपने अनुभव और पहलों को साझा करेंगी।

दोपहर के सत्र में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, प्रस्तुत करने और मूल्यांकन के दिशा-निदेर्शों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें परियोजना की गुणवत्ता में सुधार और समय पर मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। राज्यों से प्राप्त फीडबैक से दिशा-निदेर्शों को संशोधित करने में सहायता मिलेगी।

कार्यशाला का समापन सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सत्र के साथ होगा, जिसमें मुख्य निष्कर्षों और आगे के मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।

सरकार के आपदा से निपटने की क्षमता और जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, इस कार्यशाला से बाढ़ की तैयारियों में सुधार, बेहतर गुणवत्ता वाले बाढ़ प्रबंधन प्रस्तावों और मजबूत संस्थागत समन्वय में योगदान मिलने की उम्मीद है।

गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक की

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज रायपुर, छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

कभी नक्सली हिंसा का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है

मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा

केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं

छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे

कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से निजात पाने वाला है देश

छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास के मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में

विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (इरक्ष), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

75 साल के मोहन भागवत होने वाले हैं रिटायर? आरएसएस प्रमुख बोले- 'संघ कहे तो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं'

(जीएनएस)।

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान फर प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीति से लेकर संगठन के भीतर तक नई चर्चा छेड़ दी। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद पद छोड़ने की परंपरा की बात होती रही है, ऐसे में सवाल उठा कि क्या मोहन भागवत भी अब रिटायर होने वाले हैं? इस पर उन्होंने जो कहा, वही इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है।

भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे बिना किसी हिचक के ऐसा कर देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि काम से कभी रिटायरमेंट नहीं होता। इसी बयान ने यह साफ कर दिया कि संघ में पद और व्यक्ति से ज्यादा संगठन और उसका विचार महत्वपूर्ण है।

क्या 75 साल की उम्र में पद छोड़ने का नियम लागू होगा?

मोहन भागवत ने बताया कि उन्होंने अपने 75 साल पूरे होने की जानकारी संघ को दे दी है। इसके बावजूद संगठन ने उनसे काम जारी रखने को कहा है। यानी फिलहाल संघ उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी में बनाए रखना चाहता है। भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि फर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब किसी को जबरन रिटायर किया गया हो। संघ स्वयंसेवकों से उनकी आखिरी बूंद तक काम लेता है, लेकिन सम्मान और सहमति के साथ।

संघ में पद से ज्यादा सेवा क्यों अहम है?

फर प्रमुख ने कहा कि संघ का मूल उद्देश्य पद या प्रचार नहीं, बल्कि समाज में संस्कारों का विकास है। जरूरत से ज्यादा प्रचार दिखावे को जन्म देता है और फिर अहंकार आता है। उनके मुताबिक प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए। सही समय पर और सीमित मात्रा में। यही संघ की कार्यशैली रही है और आगे भी रहेगी।

सरसंघचालक बनने की योग्यता क्या है?

अपने भाषण में मोहन भागवत ने

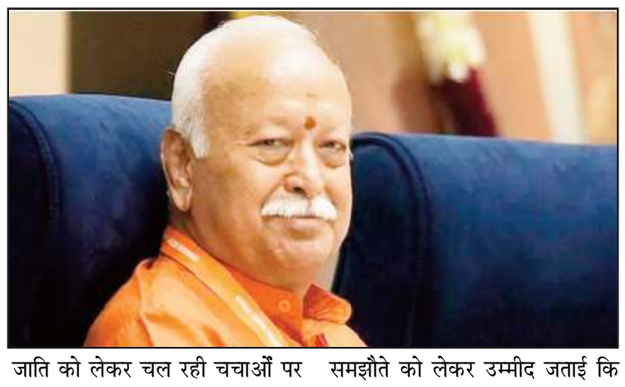

जाति को लेकर चल रही चचाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरसंघचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू समाज और संगठन के लिए काम करता है, वही इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। यह बयान संघ की समावेशी सोच को रेखांकित करता है।

सरसंघचालक बनने की योग्यता क्या है?

अपने भाषण में मोहन भागवत ने जाति को लेकर चल रही चचाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरसंघचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू समाज और संगठन के लिए काम करता है, वही इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। यह बयान संघ की समावेशी सोच को रेखांकित करता है।

UCC से लेकर घुसपैठ तक किन मुद्दों पर रखी राय?

RSS प्रमुख ने समान नागरिक संहिता पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वउउ सभी को विश्वास में लेकर बनाई जानी चाहिए, ताकि समाज में मतभेद न बढ़ें। वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने माना कि सरकार को अभी बहुत काम करना है। पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया जरूरी है। यह पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे शुरू हुई है और आगे बढ़ेगी।

भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या उम्मीद जताई?

भागवत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद जताई कि यह देश के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा और इससे भारत को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब वैश्विक व्यापार को लेकर चचाएं तेज हैं।

अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं, फर का रुख क्या है?

भाषा के सवाल पर मोहन भागवत ने साफ कहा कि फर की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी कभी मुख्य भाषा नहीं बनेगी, क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। जहां जरूरत होती है, वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। उनके मुताबिक हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषाई जड़ों से कटना नहीं चाहिए।

तो क्या मोहन भागवत सच में रिटायर होंगे?

मोहन भागवत के बयान से इतना तो साफ है कि उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला खुद पर नहीं छोड़ा है, बल्कि संगठन पर छोड़ा है। फिलहाल संघ उन्हें काम जारी रखने को कह रहा है।

लखनऊ की गोमती नदी में उतरेगा लग्जरी टूरिस्ट क्रूज, 200 सैलानियों की सुविधा के साथ ये रहेंगी खासियतें

(जीएनएस)।

नवाबों का शहर लखनऊ की पहचान में जल्द ही एक और पर्यटन आकर्षण जुड़ने जा रहा है। गोमती नदी में अत्याधुनिक टूरिस्ट क्रूज का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसमें एक साथ 200 लोग नदी की सैर का आनंद ले सकेंगे।

अभय सिंह राठौड़, लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। गोमती नदी में आलीशान टूरिस्ट क्रूज चलाने की तैयारी है। इसको लेकर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि क्रूज का संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच में किया जाएगा, जो कि 30 से 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। हनुमान सेतु के पास गोमती रिवर फ्रंट पर क्रूज के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। ये परियोजना पूरी तरह से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की जा रही है।

क्रूज में ये सुविधाएं मिलेंगी

क्रूज की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसमें एक बार में 200 लोग सवार होकर नदी की सैर कर सकेंगे। क्रूज के बेसमेंट में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजिटल स्क्रीन और वीआईपी लाउंज होंगे। वहीं, ऊपरी हिस्से में ओपन रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। क्रूज की सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये टिकट प्रस्तावित है। लंच, डिनर और बुफे की सुविधा के लिए अलग से भुगतान करना होगा। टूरिस्ट क्रूज पर कैप्टन समेत 5 मरीन क्रू-मेंबर्स तैनात होंगे। इसके साथ ही राइड शुरू होने पर कैप्टन द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए क्रूज पर मौजूद लोगों को संबोधित किया जाएगा।

5 महीने में शुरू हो जाएगा संचालन

इसके अलावा बच्चों को क्रूज की विशेषताओं और संचालन के साथ ही मरीन लाइफ के बारे में रोचक जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए तरह-तरह की मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी। इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज का संचालन 5 महीने में शुरू हो जाएगा। यह शहर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा। रविवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 5 महीने में क्रूज का निर्माण पूरा करके इस संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

कंपनी एलडीए को हर साल 16 लाख देने होंगे

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती पर टूरिस्ट क्रूज के संचालन के लिए आरएफपी आमंत्रित किया गया था। जिसके माध्यम से कोलकाता की कंपनी मेसर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा इंटरप्राइजेज का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज का निर्माण लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। जिसका पूरा खर्च कंपनी की ओर से उठाया जाएगा। क्रूज का संचालन शुरू होने पर कंपनी को प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये एलडीए को रेवेन्यू के तौर पर देने होंगे।